(ग) अनेक योजनाओं के तहत, जिनमें सेमफैक्स–1, सेमफैक्स–2 और सेमफैक्स–3 प्रमुख हैं, स्व-रोजगार कार्य शुरू करने के लिए सुविधाएं प्राप्त करने की पात्रता । पेट्रोलियम उत्पाद एजेंसियों का आबंटन, यनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एजसियों का आबंटन, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए परिवहन एजेंसियों के आबंटन आदि जैसी अनेक ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ ये पेंशनर भी प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) सैनिक अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं ।

(ङ) कैंटीन-सुविधाएं ।

(च) आवश्यकता होने पर, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, सेना मुख्यालयों और अन्य संठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करने की पात्रता ।

(छ) युद्ध में निशक्त हुए पेंशनरों के बच्चों को शिक्षा संबंधी रियायतें दी जाती हैं जैसे प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम तक शिक्षा शुल्क तथा अन्य शुल्कों, छात्रावास प्रभा र और किताबों तथा अन्य लेखन-सामग्री की मदों की कीमत और वर्दी की कीमत आदि में पूरी तरह छूट दिया जाना ।

(ज) निशक्त/युद्ध में घायल पेंशनरों को कृत्रिम अंग और शल्य-क्रिया उपकरण निःशुल्क प्रदान करना ।

(झ) जो नेत्रहीन पेंशनर सैन्य सेवा के कारण नेत्रहीन हुए हों उन्हें प्रतिमाह 50 रुपये की विशेष पेंशन ।

(ट) युद्ध में घायल पेंशनरों के उपयुक्त मामलों में सतत परिचर्या भत्ता दिया जाता है चाहे उनका रैंक कुछ भी हो ।

(ठ) इसके अतिरिक्त इन पेंशनरों के लाभ के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनेक अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन इनकी स्थिति हर राज्य में अलग-अलग है ।

वाहन फैक्टरी, जबलपुर द्वारा निर्मित वाहन

*273. **श्री शिव प्रसाद चनपुरिया** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988–89, 1989–90 और 1990–91 के दौरान वाहन निर्माणी (वाहन फैक्टरी) जबलपुर ने कितने शक्तिमान ट्रक और कितनी जोंगा जीपें निर्मित की थीं;

(ख) उक्त फैक्टरी द्वारा निर्मित ऐसे कितने वाहन विदेशों को निर्यात किए गये और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें वे निर्यात किए गये;

(ग) वर्ष 1991 तक ऐसे वाहनों के निर्माण में कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी लगी थी ;

(घ) ऐसे वाहनों में कितने प्रतिशत विदेशी उपस्करों का उपयोग किया जाता है; और

(ङ) इन वाहनों को विदेशों में बेचने से भारत को कितना मुनाफा हुआ है ?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क)

	1988–89	1989–90	1990–91
शक्तिमान ट्रक	4,004	3,470	3,449
जोंगा जीप	1,200	865	1,071

(ख) शून्य ।

(ग) संयंत्र और मशीनरी तथा तकनालाजी के लिए 1991 तक विदेशी मुद्रा में लगभग 17 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया है। यह राशि संयंत्र और मशीन की खरीद सहित आधारभूत संरचनाओं को तैयार करने के लिए 1991 तक किए गए लगभग 67 लाख रुपये के कुल पूंजी निवेश का लगभग 25 प्रतिशत है।

(घ) शक्तिमान ट्रक —शून्य
जोंगा जीप —0.03%

(ङ) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या के लिए साक्षरता योजनायें

*274. **श्री रणजीत सिंह :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली 30 प्रतिशत जनसंख्या को साक्षर बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इस वर्ग को साक्षर बनाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां; तो आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अंत तक इस वर्ग के संभवतः कितने प्रतिशत व्यक्तियों को साक्षर बना दिया जाएगा ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) से (ग) यद्यपि गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या (जो कि कुल जनसंख्या का 30 प्रतिशत है) को साक्षरता प्रदान करने के लिए अलग से कोई विशेष स्कीम नहीं है, फिर भी उनमें से अधिकांश को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा आठवीं योजना के दौरान 15–35 वर्ष के आयु वर्ग में 110 मिलियन निरक्षरों को कार्यशील साक्षरता प्रदान करने के लिए स्कीमों के अंतर्गत शामिल कर लिए जाने की आशा है। कार्यक्रम का प्रमुख ध्यान शहरी तथा ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों तथा समाज के अन्य वंचित तबकों को साक्षरता प्रदान करना होगा। साक्षरता आठवीं योजना में महत्व दिए जाने वाले क्षेत्रों में से प्रमुख है।

Reduction in rural development outlay during the 8th Five Year Plan

*275. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI MOHINDER SINGH LATHER:

Will the Minister of PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state:

(a) whether Government propose to reduce drastically the rural development outlay during the Eighth Plan period;

(b) if so, what is the extent to which the out-lay is proposed to be reduced as against the earlier projection;

(c) what are the reasons for taking such a decision; and

(d) what is its likely impact on rural development and poverty-alleviation programmes in the various States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) No, Sir.

(b) to (d) Do not arise.